नीचे लिखे अनुसार थी :—

परियोजनाओं का ब्यौरा	तारीख, जिससे शुरू की गई
1. भारत का राजदूतावास, रियाद में चांसरी, राजदूत का आवास और 44 भारत आस्थानी कार्मिकों के आवासों का निर्माण	अगस्त 1989

देरी के कारण मूल्य में वृद्धि, यदि कोई है,

रियाद निर्माण परियोजना के लिये संविदा दिसम्बर, 1993 में 47,189,413 सऊदी रियाल (12,568,928 अमरीकी डालर और 39,65,49,689 रूपए के बराबर) थी। अमरीकी डालर में मूल्य वृद्धि केवल 0.51% थी।

निर्माण कार्य पहले ही मई, 1994 में शुरू हो गया है।

2. भारत का राजदूतावास, आबू धाबी में चांसरी, राजदूत के आवास का निर्माण	सितम्बर, 1989
3. पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर का आवास, भारत का हाई कमीशन, इस्लामाबाद के अधिकारियों और स्टाफ के लिए आवास (कुल 121 इकाईयां)	अप्रैल, 1993
4. मारीशस में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (फरवरी, 1994 में निर्माण के लिए संशोधित गुंजाइश पर आधारित नया अनुमोदन)	जनवरी, 1990

1990-91 और 1991-92 के दौरान वित्तीय कठिनाईयां की वजह से निर्माण परियोजनायें हाथ में नहीं ली गई थीं। खाड़ी के संकट की वजह से रियाद और आबूधाबी की परियोजनाओं पर अमल में विलम्ब हुआ, क्योंकि खाड़ी युद्ध के बाद ठेकेदारों की पूर्व योग्यता और संविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर नये सिरे से काम करना पड़ा। ऊपर क्रम संख्या 2 से 4 तक के निर्माण प्रस्तावों पर विभिन्न प्रशासनिक वित्तीय बजट संबंधी तकनीकी और कानूनी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी विचार किया जा रहा है। ऊपर क्रम संख्या 2, 3, 4 के प्रस्तावों पर वैचारिक कार्रवाई करने में अगर समय लगने के कारण मूल्य में कोई वृद्धि होगी, तो उसके बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है क्योंकि ये निर्माण कार्य अभी ठेकदारों को दिए ही नहीं गए।

प्रधान मंत्री की सिंगापुर और वियतनाम यात्रा

1112. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :**
श्री वी० नारायणसामी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में सिंगापुर और वियतनाम की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी इन देशों के नेताओं के साथ किन-किन मुद्दों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ङ) क्या सिंगापुर और वियतनाम ने कश्मीर के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया था ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) इन देशों से पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी, हां । 5 से 9 सितम्बर, 1994 तक ।

(ख) प्रधान मंत्री ने सिंगापुर और वियतनाम के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया था इस विचार-विमर्श के परिणामत: प्रत्येक पक्ष ने एक-दूसरे के दृष्टिकोण को अधिक अच्छे ढंग से समझा और ये देश अपेक्षाकृत एक दूसरे के अधिक नजदीक आए ।

(ग) और (घ) इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर हुए :

सिंगापुर :

दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच परामर्श से संबद्ध समझौता ज्ञापन जिसमें सभी महत्वपूर्ण मसलों पर समय-समय पर विचार-विमर्श की व्यवस्था है ।

वियतनाम :

(i) दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच परामर्श से संबद्ध समझौता ज्ञापन जिसमें सभी महत्वपूर्ण मसलों पर समय-समय पर विचार-विमर्श की व्यवस्था है ।

(ii) दोहरे कराघान के परिहार के संबंध में करार ।

(iii) दोनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा सुविधाओं के संबंध में करार ।

(iv) रक्षा सहयोग के संबंध में प्रोटोकोल ।

निगमित कम्पनियों के बीच भी कई करार संपन्न हुए जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ङ) जी, नहीं ।

(च) लागू नहीं होता ।

(छ) निवेश अवसरों और भारत सरकार की नीतियों के विषय में सूचना के नियमित तथा सामयिक प्रचार-प्रसार आर्थिक प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, व्यवसाय संपर्कों को सुविधाजनक बनाना, हमारे आर्थिक सुधारों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए सतत् प्रयास कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनका उद्देश्य पूंजीनिवेश को आकर्षित करना है ।

विवरण

निगमित कम्पनियों के बीच संपन्न करारों का ब्यौरा

सिंगापुर :

सितम्बर, 1994 में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान निगमित क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित समझौता ज्ञापन/करार संपन्न हुए :

1. एक्वाफार्म : ब्लू थे मेरीन फूड्स लिमिटेड, मद्रास तथा एशिया पैसीफिक सी फूड्स प्रा० लिमिटेड, सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम ।

2. तृतीय देश व्यापार और निवेश : ग्रीवज लिमिटेड, बम्बई और पेसीफिक ग्रीवज (प्रा०) लिमिटेड, सिंगापुर के बीच सहयोग करार ।

3. शिप ब्रोकिंग : मैसर्स गणपत राय जयगोपाल बम्बई और थकराल इंवेस्टमेंटस होल्डिंगस (प्रा०) लिमिटेड, सिंगापुर तथा नाटस्टील ट्रेड इंटरनेशनल (प्रा०) लिमिटेड सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम ।

4. एल पी जी टर्मिनल : वेस्टर्न इंडिया ग्रुप और मैसर्स सीम वावांग इंजीनियरिंग, सिंगापुर के बीच संयुक्त विकास करार ।

5. निजी बैंक : 20वीं शताब्दी वित्त निगम और के फीनेंस इंवेस्टमेंट (प्रा०) लिमिटेड, सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम ।

6. मिनी टाउनशिप : ग्रोथ टेक्नो प्रोजेक्टस, नई दिल्ली और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलाजी सिंगापुर के बीच करार ।

7. वेयरहाउसिंग : न्यूजप्रिट ट्रेडिंग एण्ड सेल्स कार्पोरेशन, दिल्ली और सी डब्ल्यू टी डिस्ट्रीब्यूशन लेड सिंगापुर कंसोरटियम के बीच संयुक्त उद्यम ।

8. रेस्तरा : पामनानी फूड्स (प्रा०) लिमिटेड और इन्वो पेसिफिक होल्डिगस, सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम ।

9. मूल्य-वर्धित नेटवर्क सेवाएं : मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा और सिंगापुर नेटवर्क सर्विसिज के बीच संयुक्त उद्यम ।

10. आफिस काम्प्लेक्स : मैसर्स यूनीटेक और ए सिंगापुर कंसोरटियम के बीच संयुक्त उद्यम ।

11. बेकरी : क्वालिटी आइस क्रीम ग्रुप, इंडिया और क्यू ए एफ लिमिटेड, सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम ।

12. दूर संचार उपकरण : आई टी आई कम्यूनिकेशंस और कामेज कम्यूनिकेशंस के बीच करार ।

वियतनाम :

सितम्बर, 1994 में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान निम्नलिखित क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर हुए :

(i) नागार्जुन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा लोंग एन प्रदेश में लगभग 180 लाख अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से शत प्रतिशत विदेशी निवेश से एक चीनी मिल की स्थापना करने के लिए करार ।

(ii) वियतनाम जनरल शुगर कार्पोरेशन और के सी पी लिमिटेड के बीच शुगर मशीनरी बनाने के लिए 50 लाख अमरीकी डालर के संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर । होंगी मिनूह शहर के नजदीक सुविधाएं स्थापित होंगी ।

(iii) मैसर्स वेस्टर्न पेक्स द्वारा वी० ओ०टी० शर्तों के तहत हाची मिनूह शहर में एक मल-जल शोधन संयंत्र लगाना । होची मिनूह शहर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ करार संपन्न हुआ ।

(ii) मैसर्स राइट्स और वियतनाम नेशनल रेलवे के बीच रेलवे कोच निर्माण के लिए करार ।

(v) के ई सी इंटरनेशनल और कोम्बा इंजीनियरिंग कम्पनी के बीच हे फोंग के नजदीक ट्रांसमिशन टावर्स निर्माण करने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार ।

(vi) वेस्टर्न पेक्स और हनोई पीपल्स कमेटी के बीच हनोई में एक मल / जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए करार ।

Indiuu Representative's role at the IIN General Assembly

J113. SHRJT SUSHfILKUMAR SAMBHAJIRAO SH1NDF
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Indian repre^en'ative at the recent meeting of the UN General Assembly reiterated India's demand at the Non-aligned Conference in Cairo, for the 4th Special UN Session on Disarmament;

(b) if so,.in what precise terms; and

(c) the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) to (c) Indians proposal for convening the focrth special session of the General Assembly devoted to Disarmament, put forward in Cairo in May 1994, had been accepted by the NAM Ministerial Conference Accordingly, at our urging, Indonesia, in its capacity as NAM Chairman, introduced a resolution on this issue; which